चीनी भाषा में महाभारत और वेद-उपनिषद

हिंदी के डिग्रीधारियों को चीनी कंपनियां नौकरी दे रही हैं, भारतीय नहीं

संपन्नता की दौड़ में तेजी से भाग रहे चीनियों के लिए जहां अमेरिका और अंग्रेजी आकर्षण का केंद्र हैं, वहीं भारत तथा उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति भी लगाव रखने वाले युवा हैं। बीजिंग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक और छात्र साधना की तरह हिंदी अध्ययन-अध्यापन कर रहे हैं। तुलसी, प्रेमचंद, कालिदास के ग्रंथों के चीनी भाषा में अनुवाद का काम भी इसी हिंदी विभाग ने किया। *महाभारत* का चीनी अनुवाद अगले दो महीने में प्रकाशित हो जाने की तैयारी है। हिंदी विभाग के अध्यक्ष जांग जिंग ख्वी के अनुसार हिंदी-चीनी शब्दकोश पर दस वर्षों से काम चल रहा है। विभाग में करीब 30 छात्र हिंदी भाषा में बी.ए., एम.ए. की डिग्री के लिए प्रवेश लेते हैं। वे केवल भाषा पर ही काम नहीं करते, बल्कि हिंदी तथा भारतीय साहित्य का गहराई से अध्ययन भी करना चाहते हैं। विभाग में पांच चीनी प्राध्यापक हैं और भारतीय भाषा विशेषज्ञ के रूप में इस समय राकेश वत्स काम कर रहे हैं। अस्थायी रूप से आने वाले भारतीय विशेषज्ञ दो-तीन वर्षों में बदल जाते हैं।

विश्वविद्यालय में सफलता (बाएं) हिंदी विभागाध्यक्ष जांग जिंग एवं भारतीय भाषाविद् राकेश वत्स

जांग जिंग ख्वी ने बताया कि चीन में हिंदी के प्रति आकर्षण तो 1942 से ही है जब दक्षिण चीन के कुनमिंग विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जापानी आक्रमण के बाद शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई, लेकिन 1949 के बाद यह हिंदी विभाग बीजिंग विश्वविद्यालय से जुड़ गया। तब से यहां समर्पित भाव से हिंदी का पठन-पाठन हो रहा है। जांग को अब यह आशा जगी है कि भारत-चीन रिश्ते मधुर होने से अब हिंदी के चीनी छात्र आसानी से भारत की यात्रा भी कर सकेंगे। पहले इस तरह की यात्रा बहुत कठिन थी। लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है कि उदारीकरण के दौर में भारत से चीन पहुंची औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां बीजिंग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से निकले छात्र-छात्राओं को नौकरियां नहीं देतीं, जबकि चीनी, अंग्रेजी तथा हिंदी का ज्ञान बहुत उपयोगी माना जाना चाहिए। मजेदार बात यह है कि भारत के साथ व्यापार करने वाली चीनी कंपनियां हिंदी के डिग्रीधारियों को नौकरी दे रही हैं। आखिरकार, भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने से भी तो बाजार में भारत के सामान या भारतीयों की साख बढ़ेगी। इस संबंध में भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग-व्यापार परिसंघ विशेष रुचि लेकर भारतीय कंपनियों को ऐसे योग्य युवकों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

दूसरी तरफ चीन के सबसे बड़े रेडियो स्टेशन सी.आर.आई. (चाइना रेडियो इंटरनेशनल) द्वारा भारत में चीन की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन चार घंटे के रेडियो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। सन 1959 से रेडियो ने हिंदी प्रसारण की शुरुआत की तथा इसका निरंतर विकास किया। अब सी.आर.आई. ने हिंदी की वेबसाइट भी प्रारंभ कर दी है, ताकि चीन के समाचार या अर्थ तंत्र, समाज, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, शिक्षा, संगीत इत्यादि की जानकारियां भारत के हिंदी भाषी आसानी से पढ़ सकें। आखिर, उन्हें चीन को भारतीयों के बीच भी अधिकाधिक लोकप्रिय तथा पर्यटन का आकर्षण केंद्र बनाना है।

कंपनी टीवीएस की इकाई सुंदरम फास्टनर्स ने ऑटोमोबाइल पुर्जों के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री केंद्र के रूप में शंघाई के पास हेयान काउंटी में लगभग एक वर्ष पहले अपना कारखाना लगाया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी कंपनियों को भारत की तरह किसी लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से नहीं निपटना पड़ा। कंपनी के प्रमुख ए. नटराजन ने बताया कि कारखाने के लिए बिजली, पानी या आवश्यक संसाधनों तथा प्रशासनिक औपचारिकताओं के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों ने कंपनी के कार्यालय में बैठकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर दीं। उन्हें एक बार भी किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। तेजी से आर्थिक विकास का सबसे बड़ा राज यही प्रशासनिक चातुर्य तथा दूरगामी रणनीति है। कारखाना लगाने के लिए कोई बस्ती खाली करवाना भी कठिन नहीं है। यात्रा में शामिल एक वरिष्ठ संपादक ने टिप्पणी की, 'यहां मेधा पाटकर की तरह कोई नेता खड़ा होकर पर्यावरण या अन्य किसी मुद्दे को लेकर किसी सड़क, पुल, बांध या कारखाने का काम नहीं रुकवा सकता है।' एक दलीय शासन व्यवस्था के नुकसान जो भी हों, फिलहाल चीन की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन, बाजार, कमाई और तेजी से विकास परम लक्ष्य है। मानो पूरा देश 2008 के ओलंपिक के बाद सारे स्वर्ण पदक पाने के लिए बेताब है।

तेजी से औद्योगिक विकास के इस दौर में बीजिंग सहित देश के कई अन्य नगरों और गांवों में बिजली-संकट भी दिखने लगा है। लगभग एक खरब किलोवाट बिजली उत्पादन के बावजूद राजधानी बीजिंग की कई बस्तियों में रात को सड़कों पर ट्यूब लाइट नहीं जल पा रही हैं। अगले पांच सालों में बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार है लेकिन इस बार जून से सितंबर तक भारी लोड शैडिंग की घोषणा से हजारों कल-